BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090023

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

झारखंड में ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मूल्य और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण

Dr. Manjeet Kumar

Assistant professor, Jasidih B.Ed College, Deoghar, Jharkhand

सारांश:

झारखंड में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में काफ़ी अंतर है; जहाँ शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएँ, अधिक योग्य शिक्षक और अधिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, सीमित संसाधन और सांस्कृतिक बाधाएँ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण महिलाओं की विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के कारण, उनके लिए अधिक स्कूलों और सुविधाओं की आवश्यकता है। शिक्षा बच्चे के समग्र विकास की कुंजी है। शिक्षा ही वह वातावरण प्रदान करती है जहाँ व्यक्ति का समग्र विकास निरंतर होता रहता है। छात्र के समग्र विकास की ज़िम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षक का होता है। यह दर्शाने के लिए कि ये कारक समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, यह अध्ययन भारतीय राज्य झारखंड में ग्रामीण और शहरी महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और रोज़गार की स्थिति की तुलना करता है। एक वर्णनात्मक शोध पद्धति और 200 महिलाओं (100 ग्रामीण और 100 शहरी क्षेत्रों से) की एक नमूना आबादी का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन उल्लेखनीय अंतरों को उजागर करता है। अध्ययन दर्शाता है कि शहरी समकक्षों की तुलना में, ग्रामीण महिलाओं के पास रोज़गार के कम विकल्प हैं, वे कम शिक्षित हैं, और अपने कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति कम जागरूक हैं। इसके अलावा, महानगरीय महिलाओं में केवल 30% के पास हाई स्कूल डिग्री के समकक्ष योग्यताएँ हैं, जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह संख्या केवल 5% है।

कीवर्ड: *शैक्षिक उपलब्धि, योग्य शिक्षक, शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक अधिकारों, रोज़गार की स्थिति।*

भूमिका:

इसलिए, शिक्षण संस्थानों का यह कर्तव्य है कि वे शिक्षकों को सुविचारित और संगठित प्रशिक्षण दें ताकि वे भी अपने छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास उसके शिक्षा स्तर से काफी प्रभावित होता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा को उन्नत और मानकीकृत करने के लिए कई केंद्रीय आयोग और समितियाँ स्थापित की गईं। कई समितियों और आयोगों ने शिक्षा के समक्ष आने वाले मुद्दों की जाँच की और राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया। तीन आयोग स्थापित किए गए: शिक्षा आयोग (1964-1966), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953), और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-1949)। कोठारी आयोग ने 1951-1956 की शैक्षिक प्रगति की जाँच की और सुधार की आवश्यकता

पर बल देते हुए सिफ़ारिशें दीं। इन प्रयासों और प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई। सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का विकास शुरू हुआ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षा केंद्रित करने के प्रयास शुरू हुए। चूँकि एक बच्चे का व्यक्तित्व उसके भौतिक और प्राकृतिक परिवेश का दर्पण होता है, इसलिए अब मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक बच्चे का शक्तिशाली मन, जो असीम जिज्ञासा से भरा होता है, केवल एक स्वस्थ, शिक्षाप्रद घर और सामाजिक परिवेश में ही संतुष्ट और विकसित हो सकता है।

लोगों को सशक्त बनाने और समाज में बदलाव लाने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक शिक्षा है। यह लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण, खासकर महिलाओं के लिए, पर गहरा प्रभाव डालती है। हालाँकि, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी मुद्दों के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के शैक्षिक अवसर और उपलब्धियाँ बहुत भिन्न होती हैं। भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी शैक्षिक प्रगति में बाधा डालती हैं। जैसे, कम उम्र में शादी, लिंग के आधार पर भेदभाव, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच का अभाव और आर्थिक तंगी। हालाँकि, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संसाधनों, सुविधाओं और शैक्षिक अवसरों तक पहुँच बेहतर है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि मिलती है। इस तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण महिलाओं की कार्य स्थिति, जागरूकता और शैक्षिक उपलब्धि के बीच असमानताओं की जाँच करना है, साथ ही समाज में उनकी भूमिकाओं के परिणामों को भी ध्यान में रखना है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में असमानता का व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामान्यतः सामाजिक विकास, दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को आमतौर पर बेहतर आर्थिक संभावनाएँ, बेहतर स्वास्थ्य और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वे पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सुविचारित निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में होती हैं, जिससे सामाजिक विकास और स्थिरता बढ़ती है। दूसरी ओर, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अभाव उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों का प्रयोग करने से रोकता है, आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को कम करता है, और उन्हें गरीबी और सामाजिक अलगाव के चक्र में फँसाए रखता है। तुलना करके, इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सामने शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को उजागर करना और शिक्षा के इस अंतर को पाटने की रणनीतियाँ प्रस्तुत करना है।

अध्ययन का शैक्षिक महत्व

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक अधिकारों की समझ और रोजगार की स्थिति। अध्ययन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ सामान्य रूप से सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखेगा। उच्च स्तर की शिक्षा वाली महिलाएं सामाजिक परिवर्तन लाने में अधिक सक्षम होती हैं क्योंकि वे आर्थिक उत्पादकता, सामाजिक सामंजस्य और स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देती हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की खराब शैक्षिक योग्यता उनके योगदान को सीमित करती है, जिससे सामान्य विकास और सामुदायिक उन्नति में बाधा आती है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के शैक्षिक अनुभवों और उपलब्धियों की तुलना करके, यह अध्ययन उन संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करने का प्रयास करता है जिनका ग्रामीण महिलाएं सामना करती हैं और शिक्षा तक समान पहुँच और सशक्तिकरण के अवसरों को संबोधित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष कानून का मार्गदर्शन कर सकते हैं, साक्ष्य-आधारित

लक्षित कार्यक्रमों को सूचित कर सकते हैं, और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं।

संबंधित शोध अध्ययन

खान एट अल. (2024) ने झारखंड में उच्च शिक्षा तक पहुँच के निर्धारकों का आकलन किया और बजटीय बाधाओं, लैंगिक असंतुलन और भौगोलिक दूरस्थता जैसी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में पहचाना। उनके शोध से पता चलता है कि महिलाओं, खासकर वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में सामाजिक मानदंड शामिल हैं जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं और संस्थागत सहायता का अभाव भी शामिल है। परिणामों ने इन पहुँच संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए गैर-भेदभावपूर्ण नीतियों और विधायी परिवर्तनों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाया।

झारखंड में प्रवास के पैटर्न और प्रवृत्तियों पर कुमार और राज (2024) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अधिकांश प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण हुआ। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों, विशेषकर महानगरीय महिलाओं, को अनुकूल संभावनाएँ मिलने की संभावना अधिक थी। हालाँकि, शिक्षा के विकल्पों के अभाव में, ग्रामीण महिलाएँ पिछड़ गईं। निष्कर्ष सामाजिक-आर्थिक प्रवास और शैक्षिक असमानता के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाते हैं।

मोइत्रा (2024) ने झारखंड में उच्च शिक्षा और रोज़गार की संभावनाओं पर, विशेष रूप से आदिवासी लोगों के दृष्टिकोण से, एक यथार्थवादी मूल्यांकन किया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, आदिवासी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोज़गार की संभावनाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मोइत्रा के अध्ययन ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी झारखंड में महिलाओं की शैक्षिक सफलता को प्रभावित करने वाले स्वदेशी एजेंसी और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार करने के महत्व को स्पष्ट किया।

अध्ययन का उद्देश्य

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अध्यनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अध्यनरत विद्यार्थी की सामाजिक मूल्य का अध्ययन करना

ग्रामीण और शहरी छात्रों के शैक्षिक स्तर और उनकी सुविधाओं की गुणवत्ता की तुलना:

शहर: शहरी क्षेत्रों में उच्च-योग्य शिक्षक मिलना आसान होता है, जिससे शैक्षिक स्तर ऊँचा होता है।

ग्रामीण क्षेत्र: कुशल शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अक्सर उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।

संसाधन और अवसर:

शहरी स्थान: छात्र पर्याप्त संसाधनों के साथ-साथ शहरी स्थानों में अधिक व्यावसायिक और शैक्षिक विकल्प पा सकते हैं।

ग्रामीण स्थान: ग्रामीण स्थानों में शैक्षिक संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण छात्रों का विकास बाधित होता है।

शिक्षा में रुचि और विषय चयन:

शहरी क्षेत्र: शहरी क्षेत्रों में किशोर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के बारे में सीखने में अधिक रुचि रखते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र: अपने परिवेश के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र कृषि, गृह विज्ञान और कला जैसे विषयों के बारे में सीखने में अधिक रुचि रखते हैं।

लैंगिक असमानता और पहुँच: हालाँकि झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता में कमी आई है, फिर भी ग्रामीण छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में अभी भी अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु अधिक बालिका विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।

अध्ययन विश्लेषण एवं परिणाम

यह अध्ययन झारखंड राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित था। अपनी विविध स्थलाकृति और वित्तीय कठिनाइयों के कारण, झारखंड ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच अंतर पर शोध के लिए एक विशेष संदर्भ प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को उन जिलों से चुना गया जहाँ शैक्षिक संसाधनों और रोज़गार के अवसरों की पहुँच कम थी, जबकि शहरी केंद्रों को उन जिलों से चुना गया जहाँ सामाजिक जागरूकता संसाधनों, रोज़गार के अवसरों और शैक्षिक सुविधाओं की पहुँच अपेक्षाकृत अधिक थी। इससे दोनों समूहों की शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक अधिकारों की समझ और रोज़गार की स्थिति की सार्थक तुलना करना संभव हो पाया।

निष्कर्ष : ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

विद्यार्थियों में सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच उपलब्धि के अंतर को कम करने के लिए लक्षित नीतियों और संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

- **खान, के., अहमद, डब्ल्यू., और आलम, टी. (2024).** उच्च शिक्षा तक पहुँच के निर्धारक: झारखंड, भारत से साक्ष्य। स्टेटिस्टिका: सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था जर्नल, 104(4)।
- **कुमार, जी., और रेशमी, आर.एस. (2018)**। भारत में चयनित सशक्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्यों में शहरीकरण और विकास। झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, 16(1), 76417658। कुमार, एस., और राज, ए. (2024)। झारखंड, भारत से प्रवास की प्रवृत्ति और पैटर्न। मानविकी और सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 12(2), 8-15।

- **मोइत्रा, एन. (2024)**। आदिवासी एजेंसी के लेंस के माध्यम से झारखंड में उच्च शिक्षा और आजीविका की स्थिति की यथार्थवादी समीक्षा।
- **नारायण, बी.**, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का एक विषयवस्तु विश्लेषण: सरकार के दृष्टिकोण और कर्तव्यनिष्ठा पर ज़ोर। जनजातीय अध्ययन में बदलते दृष्टिकोण: मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से अंतःविषयता और सामंजस्य तक, 203-231।
- **नायक, के. वी., और आलम, एस. (2022)**। डिजिटल विभाजन, लिंग और शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ग्रामीण झारखंड में आदिवासी युवाओं के लिए चुनौतियाँ। निर्णय, 49(2), 223-237।
- **रवि, ए. (2021)**। भारत के झारखंड राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में मानसिक बीमारी के प्रति ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार: एक तुलनात्मक अध्ययन (मास्टर थीसिस, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (भारत))।
- **साहू, जे. के., और प्रकाश, वी. (2021)**। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के बंदगाँव ब्लॉक के निजी स्कूलों में महिला शिक्षकों के कार्य-जीवन संतुलन पर एक अध्ययन"। इंडियाना लिटरेचर, 2(10), 18-23. जर्नल ऑफ़ आर्ट्स एंड
- झारखंड - डेटा हाइलाइट्स: अनुसूचित जनजातियाँ (2001) ।
- झारखंड की जनजातियाँ, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tribes_of_Jharkhand।
- कुमार राहुल और सुमीत किशोर, (2020), झारखंड, रामगढ़ और रांची में आदिवासी बच्चों की शिक्षा।
- मिंज, दिवाकर; हांसदा, डेलो माई (2010) झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का विश्वकोश।

Citation: **Kumar. Dr. M.,** (2025) "झारखंड में ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की मूल्य और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.